प्रत्येक सोमवार को हल्द्वानी से प्रकाशित

RNI No.- UTTHIN/2017/73662

कुमाऊं जनसन्देश

www.kumaonjansandesh.com

वर्ष – 7 | अंक – 17 | हल्द्वानी(नैनीताल) | सोमवार 24 मार्च 2025 | पृष्ठ – 4 | मूल्य – 1

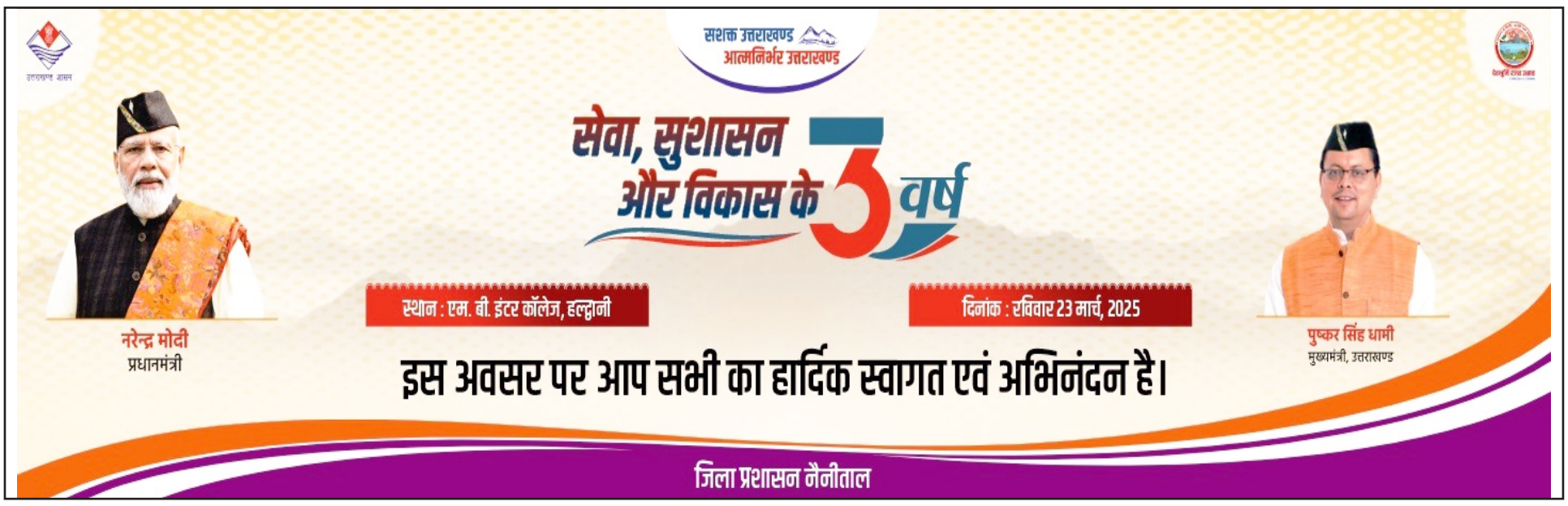

सरकार के तीन साल पूरे, उपलब्धियां गिनाई

एमबी इंटर कालेज मैदान में लगा रोजगार मेला, श्रमिकों को टूल किट भी बांटे, 28 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दौरान किया गया चयन

हल्द्वानी। राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा सुशासन एवं विकास के तीन वर्ष कार्यक्रम के तहत रविवार को एमबी इंटर कॉलेज मैदान में वृहद रोजगार मेला, श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों को टूलकिट वितरण कार्यक्रम एवं चिकित्सा शिविर लगाया गया। साथ ही विभिन्न विभागों ने स्टश्वल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी। रोजगार मेले में 17 कंपनियों ने 28 अभ्यर्थियों का चयन किया और 128 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के लिए सूचीबध किया जिनका साक्षात्कार आगामी कुछ कार्य दिवसों में लिया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उपस्थित लोगों को लाइव वर्चुअल सम्बोधित किया।

इससे पहले कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभार्थियों, 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। बहुउद्देश्यीय शिविर में विभिन्न स्टालों के माध्यम से स्थानीय लोगों को विभागीय योजना का लाभ प्रदान किया गया। स्वास्थ्य विभाग की और से लगाए गए शिविर में हल्द्वानी समेत दूरदराज से आए लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई जिसमें 185 लोगों का निशुल्क जांच की गयी। इस अवसर पर राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका सेवा, सुशासन और विकास के तीन वर्ष का विमोचन भी हुआ। साथ ही राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जनपद नैनीताल की ओर से प्रकाशित पुस्तिका उजाले की ओर बढ़ते कदम एवं लखपति दीदी कैलेंडर का भी विमोचन सांसद अजय, मेयर गजराज बिष्ट, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, दर्जा मंत्री डा. अनिल कपूर डब्बू ने किया।

कार्यक्रम में विभिन्न लाभार्थियों सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के साथ ही योजनाओं का लाभ दिया गया। जिसमें स्वच्छता एवं ठोस प्रबंधन हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों, कृषि उद्यानिकी, दुग्ध पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन आदि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार श्रम विभाग की ओर से भवन निर्माण श्रमिकों को टूल किट वितरित किए गए। महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट वितरित किए गए।

विकास विभाग की ओर से विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों को व नगर निगम द्वारा बैणी सेना समूह की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खेल विभाग की ओर से 38वे राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत 8 पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग/उपकरण निशुल्क प्रदान किए। इस मौके सांसद अजय भट्ट ने अपने संबोधन में बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में हर बच्चे का सर्वांगीण विकास होना जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया की आवश्यकता बन गई है।

उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि आज महिलाएं सेना, पुलिस, परिवहन सहित हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रही हैं। उन्होंने नकल विरोधी कानून पर भी चर्चा करते हुए कहा कि इस कानून से युवाओं को निष्पक्ष प्रतियोगिता का अवसर मिल रहा है जिससे वे सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा पारित भू-कानून पर कहा कि यह उत्तराखंड के नागरिकों के लिए लाभकारी होगा।

इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने शिविर में लगे रोजगार से संबंधित एवं अन्य विभागों के स्टालों का निरीक्षण करते हुए जानकारी ली। इस बीच मीडिया से बातचीत उन्होंने हुए कहा कि धामी सरकार के यह तीन साल उपलब्धियों भरे रहे है। धामी सरकार ने एक इतिहास बनाया है जिसमें अनेकों विकास कार्यों के साथ ही नए कानून बनाने में धामी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए।

मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि आने वाले समय में हल्द्वानी नगर में अनेक विकास कार्यों को संपन्न कर नगर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, दर्जा मंत्री दिनेश आर्य, प्रशासक जिला पंचायत बेला तोलिया, आयुक्त दीपक रावत, सीडीओ अशोक कुमार, एडीएम एफआर चौहान, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, नगर आयुक्त रिचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा मौजूद रहे।

लालकुआं में बहुद्देशीय शिविर का सैकड़ों ने उठाया लाभ

सरकार की योजनाओं की भी दी जानकारी

लालकुआं। उत्तराखंड सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और विकास के तीन वर्ष कार्यक्रम के तहत लालकुआं में लगे बहुद्देश्यीय शिविर के दौरान सैकड़ो लोगों ने विभिन्न स्टालों में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया, साथ ही विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्रवासियों को जागरूक किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल उद्बोधन देते हुए सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाई, वहीं क्षेत्रीय विधायक डा. मोहन सिंह बिष्ट समेत तमाम भाजपा नेताओं ने सरकार द्वारा 3 साल के भीतर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का बखान किया। राजकीय इंटर कालेज लालकुआं के प्रांगण में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का विधिवत शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डा. मोहन सिंह बिष्ट ने किया, इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में इन तीन वर्षों के भीतर बहुत ही तेजी से विकास कार्य हुए हैं, जिनका क्षेत्रवासी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक नवीन दुम्का, नगर पंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी, वरिष्ठ युवा भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी, दिनेश खुल्बे ब्लाक प्रमुख रूपा देवी, मंडल अध्यक्ष अरुण जोशी, रोहित दुम्का, नवीन पपोला, पान सिंह मेवाड़ी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट, भाजपा नेता धन सिंह बिष्ट, राजकुमार सेतिया, संजीव शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला, लाल चंद्र सिंह, बॉबी संभल, प्रकाश गजरौला, मनीष बोरा, अभिषेक शर्मा, विनोद श्रीवास्तव, जगदीश अग्रवाल, जीवन कबड़वाल, उप जिलाधिकारी तुषार सैनी, तहसीलदार युगल किशोर पांडे, रजिस्ट्रार कानूनगो मोहित बोरा, कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दिनेश फर्त्याल, खाद्य पूर्ति निरीक्षक मोहित कठायत मौजूद रहे।

सम्पादकीय...

जल संकट से बचने के उपायों की उपेक्षा

इस वर्ष मौसम ने होली से पहले ही तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अब जितनी अधिक गमह्न होगी, पीने, स्नान, खेत और कारखानों आदि के लिए उतनी ही जल की मांग बढ़ेगी। धरती पर पानी की जरूरत या तो बरसात से पूरी होती है या फिर ग्लेशियरों से। गमह्न के अनियंत्रित होने से इन दोनों जल स्रोतों का गणित बिगड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की तीखी मार के चलते बरसात का मौसम अब अनिश्चित-सा हो गया है। अभी से अधिकांश छोटी नदियां सूख गई हैं। इसका सीधा असर तालाबों, कुओं, नहरों और बावड़ियों पर दिख रहा है।देश में अत्यधिक जल दोहन तथा अकुशल प्रबंधन के कारण भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हमें इस जल संकट से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी। तैयारी का कोई जटिल फार्मूला नहीं है। बस हमें पुरखों ने पानी की हर बूंद को सहेजने के जो जंतर दिए थे, उन्हें सि) कर रखना होगा। भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, जबकि देश में पीने योग्य जल संसाधनों का मात्र चार प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है और देश के लगभग 70 प्रतिशत जल स्रोत प्रदूषित हैं। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2050 तक हमारी जल की आवश्यकता 1,180 अरब घन मीटर होने की संभावना है। देश में जल की उपलब्धता वर्तमान में 1,137 अरब घन मीटर है। 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी को पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होगा। यदि भारत के ग्रामीण जीवन और खेती को बचाना है तो बारिश की हर बूंद को सहेजने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अनुभव बताता है कि भारी भरकम बजट, राहत, नलकूप जैसे शब्द जल संकट का निदान नहीं हैं। करोड़ों-अरबों की लागत से बने बांध सौ साल भी नहीं चलते, जबकि हमारे पारंपरिक ज्ञान से बनी जल संरचनाएं उपेक्षा, बेपरवाही के बावजूद आज भी पानीदार हैं। हमारे देश की नियति है कि थोड़ा ज्यादा वर्षा हो जाए तो पानी समेटने के साधन नहीं बचते और कम बारिश हो तो ऐसा रिजर्व स्टाक नहीं दिखता, जिससे काम चलाया जा सके। देश के बहुत बड़े हिस्से के लिए अल्प वर्षा नई बात नहीं है और न ही वहां के समाज के लिए कम पानी में गुजारा करना, लेकिन बीते पांच दशक के दौरान आधुनिकता की आंधी में दफन हो गए हजारों तालाबों और पारंपरिक जल प्रणालियों के चलते ही हालात बिगड़े हैं। मध्य प्रदेश के तीन लाख की आबादी वाले बुरहानपुर शहर में कोई 18 लाख लीटर पानी प्रतिदिन एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से वितरित होता है, जिसका निर्माण 1615 में किया गया था। इस प्रणाली को 'भंडारा' कहा जाता है। हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बारिश के पानी को समेटने की कई प्रणालियां विकसित एवं संरक्षित की थीं। घरों की जरूरत यानी पेयजल एवं खाना बनाने के लिए मीठे पानी का साधन कुआं कभी घर-आंगन में हुआ करता था। हरियाणा से मालवा तक जोहड़ जमीन की नमी बरकरार रखने की प्रा—तिक संरचनाएं हैं। ये आमतौर पर वर्षा-जल के बहाव क्षेत्र में पानी रोकने के प्राकृतिक या कृत्रिम बांध के साथ छोटे तालाब की मानिंद होते हैं। तेज ढलान पर पानी की धारा को रोकने की प)ति ''पाट'' पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय रही है। एक नहर या नाली के जरिये किसी पक्के बांध तक पानी ले जाने की प्रणाली ''नाड़ा या बंधा'' अब देखने को नहीं मिल रहा है। कुंड और बावड़ियां महज जल संरक्षण के साधन नहीं, बल्कि हमारी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना भी रही हैं। आज जरूरत है कि ऐसी ही पारंपरिक प्रणालियों को पुनजह्नवित करने के लिए खास योजना बनाई जाए एवं इसकी जिम्मेदारी स्थानीय समाज को दी जाए। यह देश-दुनिया जब से है, तब से पानी एक अनिवार्य जरूरत रही है और कम बरसात, मरुस्थल जैसी विषमताएं प्रकृति में विद्यमान रही हैं। भूख या पानी के कारण लोगों के अपने पुश्तैनी घरों से पलायन की बातें बीते दो सौ साल से सुनने को मिल रही हैं। उसके पहले का समाज तो हर तरह की जल-विपदा का हल रखता था। समस्या यह है कि आज कस्बे-शहर में बनने वाली योजनाओं में पानी की खपत एवं आवक को कोई नहीं आंक पाता है। हमारे देखते-देखते ही घरों के आंगन, गांव के पनघट एवं कस्बों के सार्वजनिक स्थानों से कुएं गायब हुए हैं। बावड़ियों को हजम करने का काम भी आजादी के बाद ही हुआ। ऐसे ही कर्नाटक में कैरे, तमिलनाडु में ऐरी, नगालैंड में जोबो तो लेह-लद्दाख में जिंग, महाराष्ट्र में पैट, उत्तराखंड में गुल, हिमाचल में कुल और जम्मू में कुहाल कुछ ऐसे पारंपरिक जल-संवर्धन के सलीके थे, जो आधुनिकता की आंधी में कहीं गुम हो गए। अब जब पाताल का पानी निकालने एवं नदियों पर बांध बनाने की जुगत फेल होती दिख रही है तो फिर उनकी याद आ रही है। कुल मिलाकर जल को सोच-समझकर खर्च करना तो जरूरी है ही, आकाश से गिरी हर बूंद को सहेजने के लिए पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों को जीवित करना भी अनिवार्य है। ये प्रणालियां महज पानी नहीं सहेजेंगी, धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित भी करेंगी।

बागेश्वर में उत्सव के रूप में मनाया गया जन सेवा दिवस

सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों प्रमुख योजनाओं,उपलब्धियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया

बागेश्वर। राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन सेवा दिवस को उत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने रिबन काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों प्रमुख योजनाओं,उपलब्धियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान,लगभग तीस से अधिक रेखीय विभागों ने अपने विभागीय स्टॉल स्थापित किए,और नागरिकों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों को चेक वितरण व कृषि यंत्र,उपकरण,दवाइयां,बीज आदि वितरित किए गए। साथ ही चिकित्सा शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। और डश्वक्टरों द्वारा आवश्यक परामर्श दिया गया। राज्य स्तर देहरादून में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को बागेश्वर में सजीव प्रसारण के माध्यम से देखा गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित सेवा,सुशासन और विकास के 3 वर्ष पुस्तक का विमोचन किया गया।

मुख्य अतिथि विधायक सुरेश गढ़िया ने जिले के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को पूरी प्रतिब)ता और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। विधायक ने सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे है। सड़क,शिक्षा,स्वास्थ हो या फिर रोजगार देने की बात हो उन्होंने हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ा है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रदेश सरकार लोगों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में शहीद दिवस का महत्व भी रेखांकित किया और कहा कि यह दिन उन वीर सपूतों को याद करने का है,जिन्होंने देश की आन,बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने अपने संबोधन में सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून के लागू होने से बीस हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। भतह्न प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। राज्य में सशक्त भू-कानून और यूसीसी जैसे प्रावधान लागू कर सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जिलाधिकारी ने जिले में किए जा रहे अभिनव प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बागेश्वर को हैली सेवा से जोड़ा गया है जो देहरादून व हल्द्वानी के लिए संचालित हो रही है। इससे स्थानीय लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में औषधीय सघन खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। आँकाक्षी ब्लाक कपकोट में औषधीय पौधों की खेती की शुरुआत की है। जिससे किसानों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में उद्यानीकरण के साथ ही मत्स्य उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है।

रविवार को जिला मुख्यालय में जन सेवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया,जिसकी अध्यक्षता बागेश्वर विधायक पार्वती दास ने की। अपने संबोधन में विधायक ने सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित किया। और सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों एवं सफलताओं के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। जिला पंचायत प्रशासक बसंती देव ने राज्य सरकार के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने अपने सम्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य विकास के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री बलबंत सिंह भौर्याल ने अपने सम्बोधन में सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुंखी विकास हो रहा है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल,एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के,सीडीओ आरसी तिवारी ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डा. राजीव जोशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रशासक ब्लाक कपकोट गोविंद सिंह दानू, बागेश्वर पुष्पा देवी, अध्यक्ष नगर पंचायत कपकोट गीता ऐठानी, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रभा गढ़िया, महामंत्री संजय परिहार,पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा/चेयरमैन रेडक्रॉस अध्यक्ष इंद्र सिंह फर्स्वाण, कुंदन परिहार, मनोहर राम, विक्रम शाही, दलीप खेतवाल, वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मलड़ा, रमेश पर्वतीय घनश्याम जोशी, संजय शाह जगाती, दीपा आर्या, एडीएम एनएस नबियाल, एसडीएम मोनिका, पीडी शिल्पी पंत, डीडीओ संगीता आर्या, जिला सेवायोजन अधिकारी पीसी गोस्वामी आदि मौजूद रहे।

सम्पादक : विनोद चन्द्र पनेरू
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक विनोद चन्द्र पनेरू द्वारा भीड़ापानी-ओखलकांडा प्रिन्टिंग प्रेस(मोती सिंह), भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी(नैनीताल) से मुद्रित तथा हरिपुर लालमणि पो.ऑ- देवलचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखंड) से प्रकाशित। मो. 9410354318 Email:-vinodpaneru123@gmail.com

वार्डो में सफाई न होने पर रोक दें कर्मचारियों का वेतन

आयुक्त दीपक रावत ने की नगर निगम हल्द्वानी के अंतर्गत सफाई कार्यों की समीक्षा की

हल्द्वानी। कुमाऊं कमिश्नर /सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने नगर निगम हल्द्वानी के अंतर्गत सफाई कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सश्वलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर वार्ड स्तर तक की सफाई के निर्देश अधिकारीयों को दिए। कमिश्नर ने कहा कि लीगेसी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के जरिए कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी को जो भी सहयोग की आवश्यकता है उसे प्रदान किया जाए। कमिश्नर ने सड़कों की सफाई के लिए खरीदी गई जटायु मशीन में आई तकनीकी खराबी को ठीक कर शहर की सफाई उपयोग में किया जाए। कमिश्नर ने वार्डो में तैनात सफाई कर्मचारियों की मश्वनिटरिंग के निर्देश दिए। जिसके लिए हर वार्ड में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य करने को कहा गया। साथ ही वार्डो में सफाई ना करने कर्मचारियों का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान कमिश्नर रावत ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र प्रत्येक मांह में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों का सम्मान भी किया जाए। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि गमह्न का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में नगर निगम विशेष सतर्कता बरते सफाई का विशेष ध्यान रखे। नगर आयुक्त की तरफ से खुद सुनिश्चित किया जाए कि शहर की नालियां साफ-सुथरी हों। कहीं भी गंदा पानी ना रुका हो। कुमाऊं आयुक्त ने बरसात से पहले शहर के सभी बड़े नालों की सफाई सुनिश्चित करने को कहा। अगर इस सफाई के लिए ठेकेदारों से काम लिया जाता है तो काम शुरू होने से पहले और बाद में नालों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के निर्देश दिए। इसी के आधार पर ठेकेदारों को नालियों की सफाई से जुड़ा पेमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी समय समय पर इन नालियों में सफाई कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। कमिश्नर ने प्रतिबंधित पश्वलीथीन की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाने के भी निर्देश अधिकारीयों को दिए। आयुक्त ने नगर में वैडिंग जोन बनाए जाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए शीघ्र ही वेंडिंग जोन बनाने के निर्देश दिए,ताकि निगम की आय में बढ़ोतरी हो। आयुक्त ने कहा कि नगर में 16 कूड़ेदान जो अवशेष रह गए हैं उन्हें भी धीरे धीरे खत्म करते हुए सीधे घर घर से कूड़ा एकत्रित हो इस क्षेत्र में कार्य किया जाय। कुमायूं आयुक्त ने कहा कि जो व्यवसाईक प्रतिष्ठान सामको दुकान का कूड़ा एकत्रित कर सड़क में फेंक जाते हैं उनके खिलाफ चालान की कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि नगर में वैडिंग जोन खोले जाने की तैयारी तेजी से की जाय। साथ ही नगर में नालियों में हुए अतिक्रमण को भी नोटिस जारी करते हुए हटाने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए। इस दौरान नगर निगम को आय के स्रोत बढ़ाए जाने के भी निर्देश कुमायूं आयुक्त को दिए। बैठक में नगर आयुक्त ;चा सिंह, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा मनोज कांडपाल, सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आयुक्त ने किया समस्याओं का समाधान

हल्द्वानी। आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बीती शनिवार की अपराह्न में कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में विभिन्न जनसमस्या सुनी, जिसमें पेंशन, विदेश भेजने के नाम पर ठगी, इंश्योरेंश की धनराशि न दिये जाने के साथ ही लोगों द्वारा नशे आदि के सम्बन्ध में शिकायतें आयी। जिनका आयुक्त द्वारा मौके पर समाधान किया गया। आयुक्त ावत ने पुलिस, स्थानीय प्रशासन के साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर को नशे के खिलाफ सघन चौकिंग अभियान चलाने निर्देश दिये। उन्होंने कहा जो लोग इस —त्य में लिप्त पाये जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। आयुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार का नशा मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक के साथ ही शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। इसका परिणाम असाध्य बीमारी के रूप में सामने आता है, वर्तमान समय में समाज को नशा मुक्त बनाने की महती आवश्यकता है जिसके लिए हर एक व्यक्ति को जागरूक कर नशा मुक्त समाज की स्थापना की जा सकती है। जनसुनवाई में हरीश चन्द्र निवासी भौर्सा ने बताया कि 4 जून 2024 को उनके द्वारा दो भेंस खरीदी गई। ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा भेसों का बीमा कराया गया तथा समय से बीमा की धनराशि का भुगतान भी किया गया, नवम्बर 2024 में एक भैस की मृत्यु हो गई थी लेकिन इश्योरंश कम्पनी द्वारा बीमा राशि का भुगतान नही किया गया। जिस पर आयुक्त ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जांच कर शीघ्र बीमा की धनराशि दिलाने के निर्देश दिये। बिमला क्वीरा निवासी हल्द्वानी ने बताया कि उन्होंने चिकित्सा विभाग में नौकरी की लेकिन रिटायरमैंट के बाद एनपीए की पेंशन नही मिलने की शिकायत की। चिकित्सा विभाग लेखाकार के द्वारा बताया गया कि श्रीमती बिमला क्वीरा के अभिलेख पूर्ण नहीं होने के कारण भुगतान नही हो पाया। आयुक्त ने चिकित्साधीक्षक को शीघ्र अभिलेख पूर्ण कर भुगतान करने के निर्देश मौके पर दिये। जनसुनवाई में अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया।

हल्द्वानी में 21 जून से शुरू होगी सिटी बस सेवा

रीजनल ट्रांसपोर्ट एथारिटी की बैठक में आयुक्त दीपक रावत ने दी मंजूरी

हल्द्वानी। शहर में 21 जून से सिटी बस सेवा शुरू हो जाएगी। आयुक्त/ सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने सर्किट हाउस काठगोदाम में रीजनल ट्रांसपोर्ट एथश्वरिटी की बैठक में बस सेवा को मंजूरी दे दी है। जून के अंत से हल्द्वानी शहर में सिटी बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। यह निर्णय आयुक्त दीपक रावत ने रीजनल ट्रांसपोर्ट एथारिटी की बैठक में लिया है। सिटी बस प्राइवेट अश्वपरेटर चलाएंगे। जिन्हें बस खरीदने के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है। बीती मंगलवार को काठगोदाम सर्किट हाउस मैं हुई आरटीए की बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 जून से हल्द्वानी में सिटी बसें शुरु होंगी। जिनके लिए रूट तय किए गए हैं। कुल मिलाकर हल्द्वानी में 168 किलोमीटर के दायरे में सिटी बसें चलाई जाएंगी।

आयुक्त ने कहा कि इस सेवा के तहत शहर के बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के साथ-साथ नई बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी बसें पर्यावरण के अनुकूल सीएनजी अथवा बीएसवीआई पर आधारित होंगी, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सभी बसों में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इन बसों को विशेष पहचान चिह्न दिए जाएंगे ताकि यात्रियों को इन्हें आसानी से पहचाना जा सके साथ ही बस में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, कलर बोर्ड, रूट नम्बर बडे अक्षरों में अंकित किया जायेगा। बस का कलर एक ही रंग का होगा। उन्होने बताया कि नगर बस सेवा के संचालन को चरणब) तरीके से लागू किया जाएगा। बसों का संचालन सर्दियों में सुबह 8बजे से रात 8:30 बजे तक और गर्मियों में सुबह 6:30 बजे से किया जाएगा। बैठक में नैनीताल शहर में भी ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर भी चर्चा की गई। नैनीताल शहर के मौजूदा वन-वे सिस्टम के अनुरूप नगर बसों के संचालन की योजना बनाई जा रही है। यह योजना शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। बैठक में आरटीओ द्वारा 9 जनवरी के बाद जारी किए गए नए परमिटों की समीक्षा भी की गई । यह बैठक नगर बस सेवा के संचालन, ट्रैफिक प्रबंधन और नई बस योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार आएगा। बैठक में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों मे 35 रूटों में बस संचालन की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में रोडवेज, केमू एवं निजी बस संचालकों द्वारा जिन रूटों पर वाहनों का संचालन हेतु आवेदन किया गया उन स्थानों के लिए सर्वे रिपोर्ट के स्वीकृति के आधार पर बस संचालन की अनुमति दी गई। आयुक्त ने कहा कैंचीधाम मन्दिर हेतु हल्द्वानी से नई शटल बसों का संचालन शीघ्र ही किया जायेगा इसके लिए 25 केमू एवं निजी वाहनों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। बैठक में आरटीओ संदीप सैनी, गुरदेव सिंह, मनोनीत सदस्य विनोद मेहरा, सूरज प्रकाश तिवारी के साथ ही रोडवेज, केमू एवं निजी बस एसोशिएसन के प्रतिनिधि मौजूद थे।

जनसमस्याओं का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता : धामी

रुद्रपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते बुधवार को वर्चुअल सी.एम हेल्पलाईन-1905 व मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हैल्प लाईन व मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु सरकार संवेदनशील व कटिब) है। जन समस्याओं का निस्तारण करना सरकार की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी जन समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए त्वरितगति से सामाधान करना सुनिश्चित करें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन्होने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सीएम पोर्टल व मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करें व ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि शिकायत जिस अधिकारी के स्तर की है, उनका समाधान उनके स्तर पर ही हो जाय। अनावश्यक रूप से शिकायतें उच्च स्तर पर न आये। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बीडीसी और तहसील दिवसों का आयोजन नियमित रूप से हो और इनमें जनपद स्तरीय अधिकारी भी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें। उन्होने सभी विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन संबंधी प्रकरणों का एक माह के भीतर निस्तारण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी को भी पेंशन संबंधी प्रकरणों में कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े। विभागों के पेंशन प्रकरणों की नियमित समीक्षा के निर्देश उन्होंने मुख्य सचिव को दिये हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सी.एम हेल्पलाईन पर शिकायत दर्ज करने वाले 08 शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता भी की। बैठक में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, डीएमओ यूसी तिवारी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, सीएमओ डा. केके अग्रवाल, ओसी गौरव पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता लोनिवि हरीश चन्द्र, नगर आयुक्त नरेश चन्द्र दुर्गापाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत, मुख्य कृषि अधिकारी डा. अभय सक्सेना, मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. आशुतोष जोशी, महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे।

समय पर दुरुस्त कर लें सभी व्यवस्थाएं

डीएम ने ली ग्रीष्मकाल व मानसून काल की तैयारियों की बैठकं

रुद्रपुर। आगामी गीष्मकाल में सुचारू पेयजल व विद्युत एवं मानसून काल में जल भराव व बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अभी से पूर्ण तैयारियां करने निर्देश जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी भदौरिया ने सम्बन्धित अधिकारियों की ग्रीष्मकाल व मानसूनकाल की तैयारियो की बैठक लेते हुए कहा कि गमह्र का सीजन प्रारम्भ हो गया है, जैसे ही गमह्र बढ़ेगी पेयजल समस्याएं उत्पन्न होगीं। इसलिए पेयजल महकमा अपनी पेयजल लाईनो, हैण्डपम्प, नलकूपो को जहां भी मरम्मत आदि की जरूरत है उसे तत्काल करा लें ताकि जनमानस को सुचारू पेयजल उपलब्ध कराया जा सकें। उन्होने कहा फिर भी पेयजल समस्या आने पर बैकल्पिक रूप से पेयजल उपलबध कराने हेतु टैंकरों की व्यवस्था भी अभी से सुनिश्चित कर ली जाय। उन्होने विद्युत अभियंताओ को भी विद्युत लाईनो, ट्रांसफर्मो आदि की मरम्मत करने व भण्डार में अतिरिक्त ट्रांसफर्मर रखने के निर्देश दिये ताकि नलकूपो व अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफर्मर खराब होने पर तत्काल बदलकर विद्युत व्यवस्था सुचारू की जा सकें। उन्होने नगर निकायो को शहरो के सार्वजनिक स्थलो, बस अड्डो व कार्यालयो में प्याऊ, वाटर कूलर लगाने के निर्देश दिये। उन्होने स्वास्थ्य विभाग को लू लगने व गमह्र से होने वाले अन्य बीमारियों की दवाएं, ओआरएस पर्याप्त मात्रा में रखने के साथ ही सभी चिकित्सालयों में लू वार्ड व वर्न वार्ड स्थापित करने के निर्देश भी दिये। उन्होने कहा लू से बचाव हेतु जन जागरूता अभियान भी चलाया जाय। उन्होने अग्निशमन को शहरो में स्थापित फायर सिस्टम की जांच करने व वाहनों को तैयार रखने के निर्देश दिये। उन्होने सभी उप जिलाधिकारियो, खण्ड विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में वनाग्नि पर भी पैनी नजर रखने के निर्देश दिये।

कहा कि मानसून काल में जल भराव, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारिया भी अभी से कर ली जाये। उन्होने निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी सभी आवश्यक तैयारियों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर लें तथा ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पिछले वर्षो मे जलभराव एवं बाढ का अधिक प्रभाव रहा है वहश्चं पर सुरक्षात्मक कार्यो पर अधिक ध्यान दिया जाये। उन्होने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रो मे सिंचाई, लोनिवि, निकाय अधिकारियो से समन्वय बनाकर कार्ययोजना बनाते हुए नदी-नाले, नहर व शहरी क्षेत्र में नालो-नालियों की सफाई कराना सुनिश्चित करे। उन्होने सभी नगर निकाय अधिकारियो को निर्देश दिये कि प्रथम चरण में सभी नाली व नालो को 30 अप्रैल तक सफाई कराना सुनिश्चित करें तथा जीओ टैग के साथ फोटोग्राफ भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि दूसरे चरण में वर्षाकाल से पूर्व सभी नहर, नाली व नालो की दुबारा सफाई कराना भी सुनिश्चत करेगें। उन्होने सड़क महकमों को निर्देश दिये कि स्कवर, पुलिया के नीचे का मलवे की सफाई करना सुनिश्चित करेगें। इसी तरह सिंचाई विभाग को नदी, जलाशयो में जहां अधिक सिल्ट जमा हो गयी है, शीघ्र सर्वे कर ड्रेजिंग हेतु प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने और सभी निकाय अधिकारियों को अपने-अपने निकायो के नदी, नालो व नालियो का जीआईएस मैप बनाने के निर्देश दिये साथ ही उन्होने सिंचाई विभाग को पूरे जनपद के नदी, नालो, जलाशयो का जीआईएस बेस मैप तैयार करते हुए सम्भावित जल भराव व बाढ़ क्षेत्रों के समाधान हेतु लघु व दीर्घकालिन कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, ओसी गौरव पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता लोनिवि ओपी सिंह, सिंचाई बीएस डांगी, एएस नेगी, अजय कुमार जौन, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी आदि मौजूद थे।

बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाएं रोक

डीएम ने एआरटीओ, पुलिस को नियमित पर्वतन अभियान चलाने के दिये निर्देश

रुद्रपुर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए शहरी क्षेत्रों के सड़को की डिटेल सर्वे कर ब्लेक स्पश्वट्स चिन्हित करने के निर्देश दिये साथ ही उन्होंने कहा कि जो पूर्व में ब्लेक स्पश्वट्स चिन्हित किये गये थे उनमे की गयी कार्यवाही की भी समीक्षा की। उन्होने कहा जिन चिन्हित ब्लेक स्पश्वट्स में कार्यवाही कर निराकरण किया जा चुका है उन्हे ग्रीन कलर व जिनमे कार्यवाही की जा रहे है उसे पीले कलर व जिन ब्लेक स्पश्वट्स में अभी तक कार्यवाही नही हुई है उन्हे लाल कलर में दर्शाया जाये ताकि समीक्षा के दौरान आसानी से पता चल सकें व किये गये कार्यो का स्थलीय निरीक्षण भी किया जा सकें। उन्होने खतरनाक कटो को बंद करने के निर्देश दिये, साथ ही सड़क के कटो, मोड़, डायवर्जनों पर कैटआई, साइनेज, रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि ओवर स्पीड, ओवर लोडिगं, नशे में वाहन चलाने, ड्राइविंग के दौरान मोबाईल प्रयोग व भार वाहनों में यात्रियों को परिवहन करने पर प्रतिबन्द लगाने हेतु नियमित पर्वतन अभियान चलाने के निर्देश एआरटीओ, पुलिस को दिये।

जिलाधिकारी ने दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए सुरक्षा उपाय के साथ ही स्पीड लिमिट साईनेज लगाने के निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग व लोनिवि के अधिकारियों को दिये। उन्होने काशीपुर में परमानंदपुर पुल के पास आईजीएल मोड व केबीआर हश्वस्पिटल के पास सड़क दुरूस्थ करने के निर्देश पीडी एनएचएआई दिये।

अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने कहा कि सभी सड़कों के पुलिया के नीचे की सफाई करना सुनिश्चित करे ताकि वर्षा का पानी आसानी से निकल सकें। उन्होने सड़को के बीच में आ रहे विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर को हटाने के निर्देश सड़क व विद्युत महकमो को दिये। बैठक में पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर, ओसी गौरव पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता लोनिवि हरीश कुमार, अधिशासी अभियंता ओपी सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डश्व0 राजेश आर्या, पीडी एनएचएआई विकास मित्तल, एआरटीओ चक्रपाणी मिश्र, विमल पाण्डे, निखिल शर्मा, सहायक अभियंता लोनिवि पीसी पंत, मौजूद थे।

जन आवश्यकताओं के अनुरूप हों सीएसआर के कार्य

बैठक में जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक

रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों एवं जनपद में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के साथ सीद्गएसद्गआरद्ग से सम्बन्धित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर औद्योगिक इकाईयों के साथ विचार विमर्श किया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद के उद्योगों द्वारा सीद्गएसद्गआरद्ग के तहत् किये जाने वाले कार्यो के प्रस्तावों को सहयोग पोर्टल पर अपलोड करने एवं उन प्रस्तावों पर औद्योगिक इकाईयों के सहयोग से सुचारू रूप से कार्य किया जाना है। उन्होने कहा कि औद्योगिक इकाईयों द्वारा सीएसआर के तहत जो भी कार्य किये जायें उसके लिए विभागों द्वारा प्राप्त कार्यो हेतु प्रस्तावों के अनुरूप कार्य किये जाये ताकि विभागों/जनता के आवश्यकतानुसार कार्य कार्य हो सकें। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, नगर निगम, कृषि, उद्यान, कार्यक्रम, उरेडा, दुग्ध, मत्स्य, सेवायोजन विभाग, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों द्वारा अपने-अपने प्रस्तावों को विस्तृत रूप से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उपस्थित उद्यमियों के साथ साझा किये गये।

बैठक में अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन मनमोहन मैलानी, मुख्य विकास अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. केके अग्रवाल, उप नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत, मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी डा. अभय सक्सेना, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूध, जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी सहायक निदेशक मत्स्य संजय कुमार छिमवाल, महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल कमल कफल्टिया, सहित उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कपकोट में लगा आपकी सरकार आपके द्वार शिविर

बागेश्वर। कपकोट तहसील के खर्किया उनिया गैर में शुक्रवार को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय विधायक सुरेश गढ़िया एवं जिलाधिकारी आशीष भटगांई की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया और अपनी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा।विधायक सुरेश गढ़िया ने शिविर में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह शिविर क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां वे अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने लोगों से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। इस अवसर विधायक ने महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए उस ग्रामसभा को एक लाख रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की, जिनके आसपास के जंगल मे वनाग्नि की घटना ना घटित हो। जिलाधिकारी ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित विभागीय स्टालों का निरीक्षण करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की जनकल्याण कारी योजनाओं की जानकारी आमजन को देने के साथ ही लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनका यथासंभव समाधान करें।